International Journal of Financial Management and Economics

P-ISSN: 2617-9210
E-ISSN: 2617-9229
IJFME 2022; 5(2): 33-34
Received: 07-06-2022
Accepted: 13-07-2022

डॉ० बबिता वैदिक
एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, ठाकुर बीरी सिंह महाविद्यालय टूंडला, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
डॉ० बबिता वैदिक
एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, ठाकुर बीरी सिंह महाविद्यालय टूंडला, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

सकल घरेलू उत्पाद (G.D.P) का आम जनता पर प्रभाव – एक समालोचनात्मक विश्लेषण

डॉ० बबिता वैदिक

सारांश
उद्देश्य: जी०डी०पी० का आम जनता पर प्रभाव का विश्लेषण करना ।
प्रक्रिया: किसी देश की आर्थिक सेहत को मापने का एक पैमाना बना है। जिसे सकल घरेलू उत्पाद (जी०डी०पी०) कहते हैं। जी०डी०पी० से हमें एक देश की आर्थिक गतिविधियों का पता चल जाता है। किन सेक्टरों में तेजी या गिरावट आई है जी०डी०पी में गिरावट आने से आम आदमी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बेरोजगारी का खतरा बढ़ जाता है और नई नौकरियां मिलना कम हो जाता है और देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। व्यापार होटल परिवहन इन तीनों क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों पर जी०डी०पी० गिरने का असर होता है।
निष्कर्ष: यदि कुल मिलाकर कहा जाए तो जी०डी०पी के आंकड़े भले ही आर्थिक बढ़ोतरी की माया रचते हो लेकिन बढ़ोतरी का पैसा अमीरों की जेब में जा रहा है। और आम लोग बद से बदतर होते जा रहे हैं।

कूट शब्द: सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, निवेश, निर्यात, आयात

प्रस्तावना
किसी भी देश को चलाने के लिए अच्छी अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है। अच्छी अर्थव्यवस्था ही हमारे देश की तरक्की का मूलाधार होती है । किसी देश की आर्थिक सेहत को मापने का एक पैमाना बना है। जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं । सकल घरेलू उत्पाद ऐसा दर्पण है जिसमें झांक कर हम एक देश की आर्थिक स्थिति को देख सकते हैं कौन सा देश कितना समृद्ध है और धनी है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कितना है। शायद यही कारण है कि जब भी किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है तो कहा जाता है कि वह देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और जिस देश की जीडीपी घटती जाती हैं उसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता है।

सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ
सकल घरेलू उत्पाद से हमारा आशय एक देश की घरेलू सीमा में 1 वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की मौद्रिक मूल्य से है। अर्थव्यवस्था में अनेक क्षेत्रों में उत्पादन क्रिया चलती रहती है । जिसमे चीनी, कपड़ा, स्टील, खाद, गेहूं आदि वस्तुओं तथा सरकारी प्रकाशन, बैंक, बीमा तथा परिवहन आदि सेवाओं का निर्माण होता है होता है। इन समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जी०डी०पी ठीक वैसी है जैसे किसी छात्र की मार्कशीट होती है जिस तरह मार्कशीट से पता चलता है कि छात्र ने साल भर में कैसा प्रदर्शन किया और किन विषयों में वह मजबूत या कमजोर रहा उसी तरह जी० डी० पी० आर्थिक गतिविधियों के स्तर को दिखाता है कि किन सेक्टरों की वजह से इसमें तेजी या गिरावट आई है। सकल घरेलू उत्पाद का आंकलन हम निम्न तालिका से कर सकते हैं।

तालिका 1: सकल घरेलू उत्पाद 2021-22

वस्तु	मात्रा (इकाईयां)	कीमत प्रति इकाई (रु० में)	सकल मौद्रिक मूल्य (रू० में)
गेंहू	2000	300	600000
चीनी	1000	500	500000
लोहा	3000	700	2100000
सकल घरेलू उत्पाद			3200000

स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था का जी० डी० पी० रुपए 3200000 है। परंतु वास्तव में किसी देश की अर्थव्यवस्था में तीन वस्तुओं के स्थान पर सैकड़ों व हजारों किस्म की वस्तुएं और सेवाएं होती है। जिनकी कुल बाजार मूल्य को निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। सकल घरेलू उत्पाद की गणना बाजार कीमत पर किए जाने के कारण इसे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है।

सूत्र रूप में - GDP=C+I+G+[X-M]

GDP= सकल घरेलू उत्पाद
C = निजी खपत
I = सकल निवेश
G= सरकारी निवेश
X= निर्यात
M= आयात

सकल घरेलू उत्पाद की गणना-
सकल घरेलू उत्पाद की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा निम्न प्रकार से की जाती है।

व्यय के आधार पर
जी०डी०पी = उपभोग + विनियोग+ सरकारी खर्च + निर्यात – आयात

आय के आधार पर
जी०डी०पी = कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन + सकल परिचालन अधिशेष +सकल मिश्रित आय + [टैक्स प्रोडक्शन और इंपोर्ट पर दी गई सब्सिडी]

उत्पादन के आधार पर
कुल उत्पादित उत्पादों में से भेजे गए उत्पादों की गणना करके की जाती है।

सकल घरेलू उत्पाद का आम जनता पर प्रभाव
सकल घरेलू उत्पाद आम जनता के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार और लोगों के लिए फैसले करने का एक अहम फैक्टर साबित होता है। अगर जी०डी०पी बढ़ रही है। तो इसका मतलब यह है कि देश आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में अच्छा काम कर रहा है और सरकारी नीतियां जमीनी स्तर पर प्रभावी साबित हो रही है और देश सही दिशा में जा रहा है। अगर जी०डी०पी कम हो रही है तो इसका मतलब यह है कि सरकार की अपनी नीतियों पर काम करने की जरूरत है। ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद की जा सके । यदि जी०डी०पी० में गिरावट आती है तो आम आदमी पर निम्न प्रभाव पड़ता है ।

1. सकल घरेलू उत्पाद गिरने से प्रति व्यक्ति की औसत आमदनी कम हो जाएगी 2020 में अप्रैल से जून के बीच पूरी तरह लॉकडाउन था जिससे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई और रोजगार दर में भी कमी आ गई।
2. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हालात काफी बदतर हो चुके है आने वाले समय में इस क्षेत्र में परेशानियां और बढ़ सकती है मेन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में 39.3 प्रतिशत की गिरावट दिखी है ।
3. ऑटोमोबाइल सेक्टर में लाखों लोगों की नौकरियां दांव पर लग गई है अगर अर्थव्यवस्था मंदी आती है तो बेरोजगारी का खतरा और बढ़ जाता है नई नौकरियां मिलना कम हो जाता है।
4. व्यापार होटल परिवहन इन तीन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों पर जी०डी०पी० गिरने का असर होता है।
5. नौकरियों में कटौती, बढ़ती महंगाई और देश की आर्थिक दर में कमी इन तीन मोर्चों पर निराशा मिलने से लोगों की आर्थिक स्थिति पर इसका सीधा असर देखने को मिलता है।

तालिका 2: नाबार्ड 2018 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार

वास्तविक वेतन वृद्धि	
1981-82-1990-91	1990-91-2018-19
2.3%	0.5%

हर साल जी०डी०पी० के आंकड़े आते हैं। लेकिन जी०डी०पी० से आम आदमी के जीवन में क्या नफा नुकसान हुआ इसका पता नहीं चलता वित्तीय वर्ष 2021 में जीडीपी की 8. 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी सरकार और कॉरपोरेट के गठजोड़ से बनी मीडिया की हेडलाइन में कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था की रिकवरी की बात तो करती है लेकिन आम आदमी की जिंदगी पर नहीं ? वर्ष 1981 में 750 में जो सामान मिल जाता था वही सामान वर्ष 2019 में तकरीबन 15000 में मिलता है। जबकि देश में महज 10% कामगारो की महीने की आमदनी 25000 या उससे ज्यादा है । वर्ष 1991 से लेकर 2019 की हालात यह है कि कारोबारियों ने कुल मुनाफे का तकरीबन आधे से अधिक हिस्सा 58% अपने पास रखा और महज 19% हिस्सा अपने मजदूरों को दिया।

निष्कर्ष
उच्च जी०डी०पी० भारतीय नागरिकों की समृद्धि का कोई संकेत नहीं देती। वास्तविकता यह है कि जी०डी०पी० आकलन के डाटा को लेकर हमेशा विशेषज्ञों में मतभेद होते रहते हैं । हमारी जीवन स्तर को बताने वाला एक संकेतक प्रति व्यक्ति जी०डी०पी० है। लेकिन यदि कोई प्रति व्यक्ति आय के स्तर को देखें तो भारत ऐसे कई देशों से पीछे हैं जिन्हें हमने जी०डी०पी० विकास दर के मामले में काफी पीछे छोड़ रखा है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 7060 डॉलर है। वहीं फ्रांस की 43720 डॉलर और यह हम से 6 गुना से भी अधिक है। आम आदमी के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवा, पानी की व्यवस्था, स्वच्छता, शिक्षा और आय के बेहतर साधन होने चाहिए लेकिन उत्तरोत्तर सरकारों में जी०डी०पी० की दौड़ में इन कारकों को नजरअंदाज किया है। वे जिस विकास की बात करती रही वह समावेशी नहीं था। और जिस से समाज के बड़े तबके की कीमत पर सिर्फ कुछ लोगों को लाभ हुआ। आज आम आदमी का सबसे बड़ा बोझ रोज की सबसे अनिवार्य आवश्यकता भोजन पर होने वाला खर्च है। जी०डी०पी० के आंकड़े भले ही आर्थिक बढ़ोतरी की माया रचते हो लेकिन आर्थिक बढ़ोतरी का पैसा अमीरों की जेब में जा रहा है। और आम लोग बद से बदतर होते जा रहे हैं।

संदर्भ
1. अर्थशास्त्र-डॉ वी०सी० सिन्हा
2. अर्थशास्त्र-डॉ जी०सी० सिंघई
3. 9 भारतवर्ष
4. The Economics Times
5. www.b b c.com
6. https//pib.gov.in
7. www.aajtak.in